

सम्पादक के नाम

बोलने की तमीज़ ठीक करो....

जो हाँ, तलवे चाटने वाले मीडिया से इसी लहजे में बात की जाती है। एटीकेट सीखो...एटीकेट सीखो...मीडियो के एटीकेट सीखो...मैं कहता हूँ मुझे आपकी नहीं सुनती है, मुझे जनता की सुनती है...नहीं मीडिया की नहीं सुनती है...मीडिया केवल पूछ सकत है...मीडिया माध्यम है।"

सीएम खट्टर लगातार बोले जा रहे थे। जब पत्रकार ने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने कहा, "मीडिया माध्यम है...जनता की बात बताओगे तो ठीक है...बोलने की तमीज़ ठीक करो अपनी...चलो...चलो...चलो।" इतना कहकर सीएम मीडियाकर्मियों को धकियाते हुए आगे बढ़ गये।

यह घटना कल की है जब हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे सीएम विंडो से संबंधित सवाल पूछे जाने पर खट्टर पत्रकार से नाराज हो गये। जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि सीएम विंडो पर आगे वाली शिकायतों पर अधिकारी अधिकतर जल्दबाजी में मामला निपटा देते हैं। जिससे न्याय नहीं हो पाता, क्या ये आरोप सही है?

सीएम ने छूटते ही पूछा आप कौन हैं? और सीएम काफी उग्र हो गये और फिर उपरोक्त एकालाप शुरू हो गया।

- साइबर नज़र

यह इमरजेंसी का भाजपा संस्करण है

गजब जनतंत्र है। पिछली सदी की इमरजेंसी का हल्ला है और जनसभा में जन पर ही जबरिया/पुलिसिया 'ड्रेस कोड' लागू है।

'पत्रिका' में पढ़ा कि जयपुर के मौदी तमाशे में एक सिख श्रोता को पंडाल से इसलिए उठा दिया गया, क्योंकि उसकी पगड़ी का रंग काला था। तभी बैठने दिया गया जब पगड़ी पर भगवा स्कार्फ़ लपेट दिया गया। लोकतंत्र ही नहीं, आस्था से भी खिलाड़?

सुनते हैं काले रंग से चिढ़ गुजरात में पटेल समुदाय के प्रतिरोध के बाद पैदा हुई है। मगर लोकतंत्र में प्रतिरोध कबसे गैर-मुनासिब होने लगा?

लोग काले झंडे दिखाएँ, यह भी लोकतंत्र में जायज़ हक है। लेकिन काला कमीज़, बनियान, दुपट्टा, बुर्का, पगड़ी? सबकी इज्जत उतार देंगे, सरेआम? जन-संवाद (!) के नाम पर बुलावा देकर? पता नहीं बेचारे काले जूते या काली कमरपेटी पहनने वालों का क्या किया होगा।

- गिरीश मालवीय

भारत में चाईना बैंक आने के मायने?

जो जैसा सामान्य लोगों को दिखाई देता है, वह वैसा होता नहीं? सत्य को देखना, पहचाना और समझना आप आदमी के दिमाग से परे के सत्य है।

चीन को आर एस और भाजपा, तथाकथित भारत के सामान्य लोगों को, उनका सबसे बड़ा दुश्मन बतला कर पेश करती रही है।

मोदी चीन के कई चक्रवर्ती लगा चुका है जिन्हें उसके भारत के हित में किये विदेशी दोरे कहा जाता रहा है। हर बार, मोदी के जाने से पहले, सरकारी प्रचारतंत्र हमें उसके जाने के कारण भी बताता रहा है।

क्या कभी इस सरकारी प्रचार में, मोदी के जाने पहले या उसके वापिस आने पर, इस बैंक के भारत में स्थापित होने के बारे कोई भनक किसी को लगाने दी गई थी?

इसी तरह क्या कभी मोदी ने इसकी भारत के लोगों को कोई भनक लगाने दी थी?

भारत में यह बैंक लगवाने से पहले, क्या मोदी ने आर एस के चीफ मोहन भागवत से अनुमति नहीं ली होगी?

तो भारत के उल्लंघन और बेवकूफ समझे जाने वाले लोगों, यह इस घटना से, सदा के लिए समझ लो कि तुम्हरे ऊपर शासन करने वाले विशेष लोग कभी भी तुम्हें बैंक क्या हैं, आप पर शासन कैसे करते हैं, कौन तुम्हारे मित्र हैं और कौन दुश्मन, कौन भारत के शासकों के मित्र हैं और कौन दुश्मन वैराग्रह कर्त्ता भी भी नहीं बतलाएंगे और जो बतलाएंगे वह कभी भी सत्य नहीं होगा। इस लिए इन पर और इनके सरकारी तंत्र के प्रचार पर विश्वास करना बंद करो? अपनी समझ का विकास करो ताकि स्वयं समझने के योग्य बन सको।

- ओम थानवी

थाईलैंड और भारत की मानसिकता में फर्क

25 जून से थाईलैंड की जनियर फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी और उनके कोच एक गुफा में फंसे थे जहाँ वे मैच के बाद घूमने गए थे। अचानक भारी बारिश के कारण गुफा के मुंह में पानी भर गया और बच्चे गुफा के अंदर 2 किलोमीटर तक चले गए। जैसे ही घटना की जानकारी मिली पूरा राष्ट्र एकजुट होकर इन्हें बचाने के लिए इकट्ठा हो गया। दो डॉक्टर गोताखोरों के साथ गए। ऑक्सिजन की लाइन बिछा दी गई। बच्चों को खाना पानी पहुंचा दिया गया। सबसे बड़ी बात कोच ने बच्चों के माँ बाप से माफी मांगी और बच्चों के माँ बाप ने तत्काल कोच को संदेश भेजकर उन्हें अपराधबोध से मुक्त कर दिया।

पहले ये बताया जा रहा था कि बच्चों को 2 से 3 महीने तक गुफा में ही रहना पड़ेगा लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर के 6 गोताखोरों ने 2 स्थानीय गोताखोरों के साथ मिलकर सभी बच्चों और कोच को निकाल लिया गया।

अब यदि यह घटना भारत में हुई होती तो क्या होता? सबसे पहले एक बड़ी भीड़ कोच के घर को घेर लेती, उसके माँ बाप भाई बहिन पती के साथ मारपीट करती, उसके घर में आग लगा देती। पूरा देश विशेष बनकर व्हाट्सएप फेसबुक पर अपने, सुशाव देने लगता। टीवी चैनल तत्काल 6 का पैनल बनाता, जिसमें 2 मुस्लिम विद्वान 2 हिन्दू विद्वान, 1 मुस्लिम धर्मगुरु, 1 हिन्दू धर्मगुरु और विशेष आमंत्रित एक पत्रकार भी रहता और बहस शुरू हो जाती। पूरे देश के मर्दियों में पंडित जी विशेष पूजा, हवन, और महा मृत्युंजय का जाप शुरू करवा देते।

अंत में फैज़ को बुलाया जाता और आपरेशन बचाव शुरू किया जाता। और यदि बच्चे बच जाते तो क्रेडिट लेने की और एक दूसरे को जलील करने की होड़ शुरू हो जाती।

- कोलंबा कालीधर

15-21 जुलाई 2018

61 लाशें, मगर कहानी सबकी एक जैसी

अजय सिंह

अंग्रेजी में एक कहावत है, जिसका कामचलाऊ तर्जुमा कुछ इस तरह होगा: जो लोग मर गए हैं, वे अपनी कहानी नहीं कह पाते। क्या वे 61 लोग, जो उत्तर प्रदेश में 20 मार्च 2017 से 7 जुलाई 2018 के बीच तथाकथित पुलिस मुठभेड़ों में मार डाले गए, अपनी-अपनी कहानी कह पाएंगे? मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि 90 प्रतिशत से ज्यादा इस तरह की मुठभेड़ नकली व फ़र्जी हैं और इनका मक्सद कानून व व्यवस्था की स्थिति सुधारने की आड़ में पुलिस द्वारा मुठभेड़ दिखाकर लोगों की हत्या कर देना रहा है।

ऐसी मुठभेड़ों के संबंध में मानवाधिकार संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (पीयूसीएल) की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 जुलाई 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर उससे दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। इसे योगी सरकार के लिए गंभीर झटके के रूप में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया, इसका मतलब कि उसे पहली नज़र में याचिका में दम दिखा।

अपनी याचिका में पीयूसीएल ने मांग की है कि मार्च 2017 से लेकर, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी, इस साल अब तक मुठभेड़ में जितनी "हत्याएं" हुई हैं, उनकी जांच कंद्रीय जांच व्यूरा (सीबीआई) करे, और इस जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट का कोई अवकाशप्राप्त जज करे। याचिका में कहा गया है कि जिस बेलगाम छूट के साथ पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं हो रही हैं, उससे पता चलता है कि इन्हें राज्य सरकार का खुला समर्थन मिला हुआ है। याचिका में कहा गया है कि कई मौदीं पर योगी आदित्यनाथ के ऐसे बयान आये हैं, जो "मुठभेड़ हत्याओं" को जायज़ ठहराते हैं और इन्हें प्रोत्साहित करते हैं। पीयूसीएल का कहना है कि ऐसे स्थिति में राज्य पुलिस से निर्देश है, वह नहीं हुई। न एफआरआई लिखी गयी, न मजिस्ट्रीटी जांच हुई, न मुकदमा दर्ज हुआ।

जो 61 लोग इन "मुठभेड़ हत्याओं" के शिकार हुए उनमें से 27 मामलों में पुलिस विभाग ने जांच कर अपने को पाक साफ घोषित कर दिया। शेष 34 मामलों की जांच अभी होनी है, वह कुल "मुठभेड़ हत्याओं" का 50 प्रतिशत से



मार्च 2018 तक की "मुठभेड़ हत्याओं" के आंकड़े दिये गए हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के ठीक पहले के तीन सालों (2014, 2015 और 2016) में मुठभेड़ की घटनाएं कुल 16 हुईं। योगी सरकार बनने के बाद इन घटनाओं में जिस तरह अचानक बेतहाश बढ़ाती रही हुई है, उसमें लोकसभा में भी चिंता जताई जा चुकी है। पीयूसीएल ने अपनी याचिका में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा बार-बार दिये गए इस बयान को उद्धृत किया है कि अपराधी या तो जेल जायेंगे या मुठभेड़ों में मार डाले जायेंगे। याचिका में पिछले साल 19 नवंबर को दिये गए मुख्यमंत्री के बयान का हवाला दिया गया है कि राज्य में योगी आदित्यनाथ के बादहाश बढ़ाती रही हुई है, उसमें लोकसभा में भी चिंता जताई जा चुकी है। पीयूसीएल ने अपनी याचिका में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा बार-बार दिये गए इस बयान को उद्धृत किया ह